1	2	3	4
7	Nitrofan	1. Fluchloralin	
		2. Isoproturon	
		3. Alachlor	
8	Pentachlorophenol (PCP)	Paraquet Dichloride	
9	Pentachloronitrobenzene (PCNB)	Thiram	Currently, Thiram could only be the possible substitute.
10	Paraquet-dimethyl Sulphate	Paraquet Dichloride	
11	Tetradifon	1. Dicofol	
		2. Ethion	
		3. Dimethoate	
12	Toxaphene	1. BHC	
		2. Endosulfan	
		3. Chlorpyriphos	

Central assistance for drought situation in Andhra Pradesh

658. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Government of Andhra Pradesh has made a request for Rs. 500 crores relief to meet the drought situation ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) what is the amount of Central assistance sanctioned and the amount released so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) Government of Andhra Pradesh submitted a memorandum in May, 1993, seeking Central assistance of Rs. 645.44 crores for relief operations in the area affected by drought in the sectors like irrigation, agriculture, horticulture, wasteland development, sericulture, handloom, rural roads, drining water, fodder supply etc.

(c) In addition to the normal release of first quarterly instalment of Central share of Calamity Relief Fund (CRF), Government of India has released 2 advance quarterly instalments amounting to Rs. 24.60 crores for relief operations.

तिलहनों का उत्पादन

659. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन किया जाता है और इसमें से कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) वर्ष 1992–93 के दौरान विभिन्न प्रकार के तिलहनों का कितना-कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) वर्ष 1993–94 के दौरान विभिन्न प्रकार के तेलों के निर्यात का कितना-कितना लक्ष्य रखा गया है ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अनुमान

है कि 1992–93 के दौरान, 253.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तिलहनों के तहत था। नवीनतम उपलब्ध अनुमान के अनुसार, 1989–90 में तिलहन फसलों के तहत कुल 228.0 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 44.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित था।

(ख) अनुमान है कि 1992–93 के दौरान विभिन्न तिलहनों का 206.3 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 1993-94 के लिए 170.0 करोड़ रुपए मूल्य के अरण्ड तेल तथा 15.0 करोड़ रुपए मूल्य के गौण तेल (वसा) के लिए ही निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अन्य तेलों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा

660. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना पिछले अनेक वर्षों से घाटा उठाती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ठीक इसके विपरीत मदर डेरी को मुनाफा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन बेचे जा रहे दूध की तुलना में मदर डेरी की बिक्री अधिक है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि विभिन्न सरकारों द्वारा गठित समिति ने दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धन और आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(च) यदि हां, तो इन सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण है; और

(छ) मार्च, 1993 तक दिल्ली दुग्ध योजना को कुल कितना घाटा हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। इस घाटे का मुख्य कारण, दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम निर्धारित किया जाना है।

(ख) मदर डेयरी नाममात्र का मुनाफा कमा रही है वर्ष 1992–93 के दौरान मदर डेयरी ने अपने 158 करोड़ रुपए के कारोबार से 16.27 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया।

(ग) तथा (घ) 1992–93 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी के दूध की औसत बिक्री इस प्रकार है :–

दिल्ली दुग्ध योजना
4.26 लाख लीटर प्रतिदिन

मदर डेयरी
5.70 लाख लीटर प्रतिदिन

(ङ) और (च) दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए गठित सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि दिल्ली दुग्ध योजना को सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत सहकारी समिति के रूप में संगठित किया जाए। तथापि दिल्ली में दूध के बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रभाव में यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिया जाए जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के परामर्श से इसके भावी स्वरूप को तय करने का निर्णय करेगा।

(छ) नवम्बर, 1959 में इसके प्रारम्भिक गठन से लेकर अब तक दिल्ली दुग्ध योजना का अनन्तिम आधार पर आकलित घाटा 226.72 करोड़ रुपए का है।